



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—प्राप्ति 1

PART I—Section 1

प्र. विकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 154] नई विलासी, वृहस्पतिवार, जून 27, 1974/प्राप्ति 6, 1896

No. 154] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 1974/ASADHA 6, 1896

इस भाग में भिन्न प्रकार संलग्न प्री जारी हुए जिससे इस पात्र अलग संकलन के लिए भी इसका उपयोग किया जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be used as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 19th June 1974

SUBJECT.—Constitution of Inter-Ministerial Committee to review compensatory allowances for export products.

No. 12(3)/73-EAC.—Government have been feeling the necessity to have a Standing institutional arrangement to review the conditions of market for exports, and cash compensatory allowance for the export products from time to time, depending on long term and stable trends in costing and prices realised and other relevant factors. It has been decided, therefore, to constitute an Inter-Ministerial Committee to review costs of production, f.o.b. realisation, and freight rates (where freight subsidy is afforded), for the export products admissible from time to time. The Committee will consist of the following:—

Chairman

1. Additional Secretary, Ministry of Commerce.

Members

2. Additional Secretary, Department of Expenditure.

3. Additional Secretary, Department of Economic Affairs.

4. Chief Controller of Imports & Exports.

5. Director (EA), Ministry of Commerce.

6. Development Officer (E.P. Engg.), Directorate General of Technical Development.

7. Development Officer, (E.P. Chem.), Directorate General of Technical Development.

The Chairman will also have the powers to co-opt other concerned officers *ad hoc* as and when any necessity may arise. The Committee would meet once a quarter ordinarily or oftener, if necessary to consider modifications, if any, required in the

levels of cash compensatory allowance taking into account the developments that might have taken place from time to time.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

R. TIRUMALAI, Addl. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 19 जून, 1974

विषय—नियंत्रित उत्पादों हेतु प्रतिपूरक भत्तों का पुनरीक्षण करने के लिए अन्तःमंत्रालय समिति का गठन

सं. 12 (3) / ७३ई०.ए० सी०.—सरकार, लागत नियंत्रण और प्राप्त होने वाली कीमतों में संबंधित दीर्घिकार्धित तथा स्थिर प्रवृत्तियों तथा अन्य संगत कारणों पर निर्भर रहते हुए समय-समय पर बाजार परिस्थितियों और नियंत्रित उत्पादों हेतु नकद प्रतिपूरक भत्तों का पुनरीक्षण करने के लिए स्थायी संस्थागत प्रबंध करने की आवश्यकता अनुभव करती है। अतः समय-समय पर अनुग्रेड नियंत्रित उत्पादों हेतु उत्पादन लागतों, जहाज पर मूल्य प्राप्ति, और भाड़ा दरों (जहाँ कि भाड़ा उपदान दिया जाता है) का पुनरीक्षण करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

प्रध्यक्ष

- प्रपर सचिव,
वाणिज्य मंत्रालय।

सदस्य

- प्रपर सचिव,
व्यय विभाग।
- प्रपर सचिव,
आर्थिक कार्य विभाग।
- मुख्य नियंत्रक, आयात तथा नियंत्रित।
- निदेशक (ई०ए०), वाणिज्य मंत्रालय।
- विकास अधिकारी (ई०पी० इंजी०) तकनीकी विकास महानिदेशालय।
- विकास अधिकारी (ई०पी०के०) तकनीकी विकास महानिदेशालय।

जैसे ही और जब आवश्यकता होगी प्रध्यक्ष को तदर्थं आधार पर अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को सहयोगित करने की शक्तियां भी होगी। समिति की बैठक, यदि आवश्यक हो, ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए जो कि समय-समय पर हुई हों, नकद प्रतिपूरक भत्तों के स्तरों में अपेक्षित संशोधनों, यदि कोई हों, पर विचार करने के लिए साधारणतया अवधार प्रायः तिमाही में एक बार होगी।

प्रावेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रतिलिपि सभी संबद्धों को भेज दी जाए।

शार० तिरुमलाई, प्रपर सचिव।